

न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया सी.जे. और आई. एस. तिवाना, जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

कैलाशवती और अन्य,-प्रतिवादी।

1978 की नियमित प्रथम अपील संख्या 1800।

11 सितम्बर 1979

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) - धारा 23, 28 और 34 सोला टियम - क्या मुआवजे का एक हिस्सा - सोलेटियम पर ब्याज क्या देय है।

यह माना गया कि सोलेटियम एक भूमि मालिक को दिए गए मुआवजे का एक अभिन्न अंग है। एक बार, यह माना जाता है कि यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 (2) के तहत प्रदान की गई राहत भूमि मालिक को दिए गए मुआवजे का एक अभिन्न और वैधानिक हिस्सा है, फिर धारा 28 की स्पष्ट शर्तों से अधिनियम के अनुसार, यह स्पष्ट होगा कि ब्याज दिए गए मुआवजे पर देय है, न कि केवल भूमि के बाजार मूल्य पर। वास्तव में धारा 28 की भाषा अकेले बाजार मूल्य का दूर-दूर तक उल्लेख नहीं करती है और मुआवजे या उसके समतुल्य राशि की बात करती है। इसलिए, धारा 28 के तहत दिए जाने वाले ब्याज में बाजार मूल्य और वैधानिक समाधान दोनों शामिल होंगे। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि धारा 28 के प्रावधान शर्तों के साथ-साथ सोलेटियम पर ब्याज देने की भी गारंटी देते हैं और अधिकृत करते हैं।

(पैरा 9 और 10)

श्री एस. 4,293.00 से रु. 15 प्रतिशत सोलैटियम के अलावा 5,962.50 रुपये और साथ ही कब्जा लेने की तारीख से उन्हें भुगतान किए जाने तक या भुगतान के लिए अदालत में जमा करने तक, जो भी पहले हो, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और आगे आदेश दिया जाएगा कि ब्याज भी दिया जाएगा। सोलेटियम की राशि भी देय होगी।

अपीलकर्ताओं के लिए भूप सिंह, वकील के साथ यू.डी. गौड़
प्रतिवादियों की ओर से राम रंग, वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. एस. संधवालिया सी.जे.,

(1) ग्यारह नियमित प्रथम अपीलों का यह सेट, सभी हरियाणा राज्य द्वारा पसंद किया गया (नों में क्रॉस-आपत्तियों के साथ) - माना जाता है कि कानून और तथ्य के समान मुद्दों को जन्म देता है और इसलिए, इस एकल निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। 2. 1 मई, 1973 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना द्वारा, हिसार के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कुल मिलाकर 70 एकड़ क्षेत्र का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी- दिल्ली, हिसार, सिरसा और फाजिल्का को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर गुजरें। इसके बाद हुई अधिग्रहण की कार्यवाही में, कलेक्टर ने 24 दिसंबर, 1973 को अपना पुरस्कार दिया, जिसमें उन्होंने सैट रॉड गांव से निकटता या अन्यथा के आधार पर भूमि को दो ब्लॉकों में वर्गीकृत किया और मुआवजा दिया। रुपये की दर 'ए' ब्लॉक में आने वाली भूमि के लिए 6480 रुपये प्रति एकड़ की दर से। 'बी' ब्लॉक में शेष भूमि के लिए 5000 प्रति एकड़। दिए गए मुआवजे से असंतुष्ट होकर भूस्वामियों ने कई संदर्भों को प्राथमिकता दी, जिन्हें हिसार के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए समेकित किया गया था। गुण-दोष के आधार पर उसमें जो एकमात्र मुद्दे तय किए गए थे, वे भूमिधारकों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में थे और यह सामान्य मामला है कि अपीलों के इस सेट में भी यही प्रश्न एकमात्र ऐसा है जो निर्धारण के लिए आता है।

भूमि मालिक-दावेदारों की ओर से आसपास के प्रदर्शन पी. 1 से पी. 11 में बिक्री लेनदेन के 11 उदाहरण रिकॉर्ड में लाए गए थे। खंडन में प्रतिवादी-राज्य ने पंजीकृत बिक्री कार्यों और उत्परिवर्तन आर.डब्ल्यू. 1/2 से आर.डब्ल्यू. 1/13 की प्रतियों पर भरोसा किया, जो आसपास के क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण के उदाहरण हैं। इनके अलावा गवाहों की मौखिक गवाही भी पेश की गई। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पूरे रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद ब्लॉक 'ए' में मुआवजे को बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया और ब्लॉक 'बी' को बढ़ाकर रु. 6000 प्रति एकड़। 15 प्रतिशत की दर पर वैधानिक रियायत देने के अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजे पर भूस्वामियों को इस रियायत सहित 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। 4. हरियाणा राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री यू.डी. गौड़ राज्य अपीलों को दबाने में उदासीन रहे। पहली चुनौती भूमि को दो ब्लॉकों में वर्गीकृत करने के संबंध में थी। वकील ने संभाव्यता और तर्कसंगतता के साथ तर्क दिया कि कलेक्टर या विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दो बेल्ट के निर्माण के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इस वर्गीकरण को रद्द कर दिया जाए और भूमि का मूल्यांकन ब्लॉक 'बी' में दिए गए समान दर पर किया जाए। 5. उपरोक्त तर्क में कुछ योग्यता है, हालांकि अपीलकर्ता-राज्य को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। दो ब्लॉक बनाने के लिए कलेक्टर द्वारा दिया गया एकमात्र मामूली कारण यह है कि भूमि का एक हिस्सा सात रॉड गांव के नजदीक था और बाकी वहां से दूर था। ऐसा लगता है कि इस आधार पर उन्होंने एक मनमानी रेखा खींच दी है और दोनों श्रेणियों के लिए अपेक्षाकृत असमान दरों पर मुआवजा दिया है। यहां विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूमि का अधिग्रहण किसी कॉम्पैक्ट वर्गाकार या आयताकार ब्लॉक में नहीं किया जा रहा था, बल्कि शहर

को घेरने के लिए एक राजमार्ग के निर्माण के लिए एक लंबी पट्टी के आकार में किया जा रहा था। लम्बी दूरी तक हिसार की। ऐसी स्थिति में लंबी दूरी तक अधिग्रहण के लिए गिरी भूमि की अपेक्षाकृत संकीर्ण पट्टी का मूल्यांकन केवल सात रोड गांव से इसकी निकटता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर ने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने इस पहलू पर दूर-दूर तक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया था। साइट की योजनाओं और बाई-पास के ले-आउट और उससे गांव की आबादी के अपेक्षाकृत दूर के स्थान को देखने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस मनमाने आधार पर वर्गीकरण को संभवतः बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि भूमि का मूल्यांकन एक समान आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद इसके बाजार मूल्य के लिए चर्चा में यह निर्धारित करना होगा। 6. श्री गौड़ का दूसरा तर्क यह था कि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने प्रदर्श पी.डब्ल्यू. को गलत तरीके से नजरअंदाज किया था। 1/14 जो कि जिला न्यायाधीश, हिसार द्वारा एक अन्य क्षेत्र के कुछ ही दिन पहले इसी तरह के अधिग्रहण के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।

मामले के इस पहलू पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने फैसले के पैराग्राफ 20 में इस प्रकार कहा है: -

"विद्वान सरकारी वकील ने मेरा ध्यान विद्वान जिला न्यायाधीश, हिसार द्वारा पारित दिनांक 20 फरवरी, 1978 के फैसले की ओर भी आकर्षित किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य 5,000 रुपये प्रति माना गया था। एकड़। मुझे विद्वान सरकारी वकील से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है कि उक्त निर्णय प्रदर्शनी पी.डब्ल्यू. 1/14 का पालन किया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 8 में विद्वान जिला न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दावेदार ने नहीं लाया था अपने दावे के समर्थन में ऑन रिकॉर्ड संतुष्ट-फैक्ट्री साक्ष्य कि अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य 5,000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक था। जबकि, मौजूदा मामले में दावेदारों ने रिकॉर्ड पर 8 बिक्री विलेख लाए हैं। वर्ष 1973, मार्च, जुलाई और दिसंबर के महीनों से संबंधित। इसके अलावा वे 21 जनवरी, 1972 की एक बिक्री विलेख और अक्टूबर और नवंबर, 1975 से संबंधित दो बिक्री विलेख भी लाए हैं। इसलिए, इस मामले में साक्ष्य इसे उस मामले के बराबर नहीं माना जा सकता जिसके कारण विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष मामला चला जिसमें निर्णय प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/14 पारित किया गया।"

तर्क की एक ही पंक्ति को दोबारा दोहराना अनावश्यक है और यह कहना पर्याप्त है कि हम विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से पूरी तरह सहमत हैं और उपरोक्त कारणों से अपीलकर्ता-राज्य की ओर से विवाद को खारिज करते हैं।

(7) अंत में श्री गौड़ ने तर्क दिया कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सोलेटियम की राशि पर ब्याज देने में भी गलती की है। उन्होंने भारत संघ बनाम राम मेहर और अन्य¹ पर भरोसा करते हुए कहा कि ब्याज की अनुमति केवल भूमि के बाजार मूल्य पर ही दी जा सकती है, सोलेटियम पर भी नहीं। 8. अब राम मेहर के मामले (सुप्रा) का बारीकी से अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता का तर्क अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है। उक्त निर्णय में उनके आधिपत्य के समक्ष निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण (संशोधन और मान्यकरण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(3) का प्रावधान था। गोवर जे. ने बेंच में बोलते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि माइक प्रिंट एडिलेमिनेशन टे मेनिंग और एक्सप्रेसन मार्केट वैल्यू एम पिये के संबंध में था। वहाँ, यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय में जो सहमति व्यक्त की गई थी वह संशोधन और मान्यकरण अधिनियम में उपयोग के लिए बाजार प्रतीक्षा थी। यह उस विशेष परिस्थिति में था कि उनके लारिसिग्स ने माना कि बाजार मूल्य में लैटम की मात्रा शामिल नहीं है और इसलिए, धारा 4 द्वारा निर्धारित ब्याज की सीमा केवल भूमि के बाजार मूल्य तक ही सीमित थी। इसलिए, राम मेहर का मामला अपीलकर्ता-राज्य के लिए किसी भी प्रकार की सहायता का नहीं है

9. राम मेहर मामला टिप्पणियों की गहराई से जांच की और प्रतिवादी- जमीन मालिकों द्वारा उठाए गए रुख की सहायता के लिए। उनके आधिपत्य ने किसी भी दल में यह स्पष्ट कर दिया कि सुलातुम थोड़े समय के लिए वांछित मुआवजे का एक अभिन्न अंग था।

इसे इस प्रकार देखा गया:-

“ 15 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि निश्चित रूप से मुआवजे की राशि का हिस्सा बनती है क्योंकि धारा 23 के तहत मुआवजे में वह शामिल है जो उप-धारा () में प्रदान किया गया है और बाजार मूल्य पर 15 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि शामिल है। भूमि अधिग्रहण. लेकिन मुआवजा और बाजार मूल्य अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ हैं और इन्हें अधिग्रहण अधिनियम में इस तरह जोड़ा गया है...”

और फिर:-

"यदि विधायिका द्वारा बाजार मूल्य और मुआवजे का एक ही अर्थ रखने का इरादा था, तो यह समझना मुश्किल है कि धारा 28 और 34 में "मुआवजा" शब्द का उपयोग क्यों किया गया था, न कि "बाजार मूल्य" का। अर्थ की कुंजी शब्द "मुआवजा" धारा 23(1) में पाया जाता है और इसमें (ए) भूमि का बाजार मूल्य और (बी) ऐसे बाजार मूल्य पर 15 प्रतिशत का योग शामिल है, जिसके लिए विचार

¹ ए.एल.आर. 1973 एस.सी. 305.

किया गया है अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति। इसलिए मुआवजे की राशि के निर्धारण में बाजार मूल्य केवल घटकों में से एक है।-

10. एक बार जब इसे मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत प्रदान की गई सांत्वना भूमि मालिक को दिए गए मुआवजे का एक अभिन्न और वैधानिक हिस्सा बनती है, फिर अधिनियम की धारा 28 की स्पष्ट शर्तों से, यह स्पष्ट होगा कि ब्याज दिए गए मुआवजे पर देय है, न कि केवल भूमि के बाजार मूल्य पर। वास्तव में धारा 28 की भाषा दूर-दूर तक अकेले बाजार मूल्य का उल्लेख नहीं करती है और मुआवजे या उसके समतुल्य राशि की बात करती है। इसलिए, धारा 28 के तहत दिए जाने वाले ब्याज में बाजार मूल्य और वैधानिक समाधान दोनों शामिल होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि धारा 28 के प्रावधान शर्तों के साथ-साथ सोलेटियम पर ब्याज के अनुदान को भी अधिकृत करते हैं।

11. हम जो दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं, वह जियान देव बनाम हरियाणा राज्य² में इस न्यायालय के पहले एकल पीठ के फैसले के अनुरूप है। इस दृष्टि से मामले को अधिक विस्तार से बताना अनावश्यक है। यह कहना पर्याप्त है कि हम इसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क की भी पुष्टि करते हैं।

12. अपीलकर्ता-राज्य की ओर से कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया है और उसमें कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम सभी ग्यारह नियमित प्रथम अपीलों को लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर देते हैं।

अब भूस्वामियों द्वारा पसंद की गई क्रॉस-आपत्तियों की ओर ध्यान दिलाते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दावेदारों के विद्वान वकील श्री राम रंग यह तर्क देने में दृढ़ आधार पर हैं कि उनके ग्राहक स्पष्ट रूप से मुआवजे की राशि में वृद्धि के हकदार हैं, हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से प्रदर्शन पी की ओर आकर्षित है। . 1 से पी. 11 जो अधिसूचना के भौतिक समय पर अपेक्षाकृत उच्च प्रचलित केट मूल्य को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर साबित हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जो विज्ञापन दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इन उदाहरणों पर भरोसा किया है और उनकी प्रामाणिकता पर किसी भी तरह से संदेह नहीं किया है। भले ही बिक्री के कुछ उदाहरण अधिसूचना के काफी समय बाद की अवधि से संबंधित थे और उन्हें उचित रूप से विचार से बाहर रखा जाना चाहिए, फिर भी पी. 4, पी. 7 और पी. 8 प्रदर्शित हैं जिनकी प्रासंगिकता और वैधता के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इन्हें सर्वोत्तम रूप में सारणीबद्ध किया जा सकता है :

² ई.एफ.ए. 1974 के 202 का निर्णय 9 अगस्त 1975 को हुआ

दस्तावेजों का विवरण	बिक्री की तारीख	बेचे गए क्षेत्र की रकबा संख्या, खसरा नंबर	विक्रय मूल्य	प्रति एकड़ विक्रय मूल्य रूपये में
Ex. P 4, विक्रय विलेख, पंजीकरण नं - 3318 म्यूटेशन नं. 905, विक्रेता मदन लाल, करम चंद का बेटा	30-3-73	121/16 (8-0) - 8 कनाल टिब्बा	12,000/-	12,000/-
Ex. P7 - विक्रय विलेख, पंजीकरण नं - 3819, म्यूटेशन नं. 4761, विक्रेता राम चंद, लाल चंद का पुत्र	30-3-73	121/14 (8-0)	12,000/-	12,000/-
Ex. P.8 विक्रय विलेख, पंजीकरण नं . 3820, म्यूटेशन नं - 4760 विक्रेता लाल चंद	30-3-73	121/24 & 25 (16-0) & 132/9/1 (2-18)	28,000/-	11,851.85

यह उजागर करने योग्य है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वैध विचारों के लिए प्रतिवादी-राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर साबित बिक्री के उदाहरणों पर विचार करने से बाहर रखा था, जिन्हें विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई थी, और उन्होंने वास्तव में दबाव नहीं डाला था उनकी स्वीकृति के लिए. ऐसा होने पर, किसी को अनिवार्य रूप से ऊपर देखे गए

स्वीकार्य बिक्री उदाहरणों पी. 4, पी. 7 और पी. 8 पर बाजार मूल्य का आकलन करना छोड़ दिया जाता है। ऊपर देखा गया. 30 मार्च, 1973 को बिक्री के ये सभी तीन उदाहरण, अधिग्रहण की वास्तविक तारीख, 1 मई, 1973 से बमुश्किल एक महीने या उससे अधिक पहले के हैं। समय में उनकी निकटता इस प्रकार स्व-प्रमाण है। वे बड़े पैमाने पर भूमि से संबंधित हैं और लेनदेन की प्रामाणिकता पर दूर-दूर तक विवाद नहीं है। साइट योजना के संदर्भ से पता चलता है कि वे स्थान के मामले में बिल्कुल भी दूर नहीं हैं और वास्तव में उस कोण से तुलनीय भूमि का उचित मानक भी प्रदान करते हैं। अनिवार्य रूप से किसी को यह निष्कर्ष निकालना होगा कि दर्शाया गया उचित बाजार मूल्य रुपये के पूर्ण आंकड़े पर आता है। 12,000 प्रति एकड़. जैसा कि पहले देखा गया है कि कलेक्टर द्वारा बनाए गए और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा बनाए गए दो ब्लॉकों का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, भूमि का मुआवजा एक समान दर पर दिया जाना चाहिए। दर और उपरोक्त बाजार मूल्य ही उसका सही मूल्यांकन प्रतीत होता है।

14. यह स्मरणीय है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने भूस्वामी दावेदारों के विक्रय मामलों की सुनवाई के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया था:- "23. पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए उपरोक्त साक्ष्यों की बारीकी से जांच से, यह स्पष्ट है कि जबकि प्रतिवादी राज्य अपने दावे के समर्थन में कोई संतोषजनक सबूत नहीं लाए हैं कि आवश्यक भूमि का बाजार मूल्य था प्रति एकड़ 5,000 रुपये से अधिक नहीं, याचिकाकर्ताओं ने उचित और ठोस दस्तावेजी सबूतों से साबित कर दिया है कि अधिग्रहीत भूमि और उसके इलाके और आसपास के क्षेत्र में मौजूद भूमि का बाजार मूल्य, धारा के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके आसपास था। अधिनियम की धारा 4, 11,851.85 रुपये से 12,000 रुपये प्रति एकड़ के बीच थी। उन्होंने यह भी साबित किया है कि अधिग्रहीत भूमि के निकट स्थित भूमि का बाजार मूल्य 21 जनवरी, 1972 को भी 12,307 रुपये प्रति एकड़ था। अधिग्रहण से लगभग 11 साल पहले की बात है और यह 5 नवंबर, 1975 को यानी अधिग्रहण के लगभग 2 साल बाद बढ़कर 15,360.66 रुपये प्रति एकड़ हो गई थी। 24. उपरोक्त सभी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद, मेरा विचार है कि 'ए' ग्रेड भूमि के लिए रुपये की दर से मुआवजा दिया जाएगा। 9,000 प्रति एकड़ और 'बी' ग्रेड भूमि के लिए रुपये की दर से। 6,000 प्रति एकड़ बाजार मूल्य होगा। इसलिए, मुद्दा नंबर 1 तदनुसार तय किया गया है।"

15. उपरोक्त कारणों से सभी प्रति-आपत्तियाँ स्वीकार की जाती हैं। भूमि मालिक-दावेदारों को मुआवजा दिया जाता है और अन्य रुपये की एक समान दर. 12,000 प्रति एकड़. वे 10 प्रतिशत की वैधानिक दर पर सोलैटियम और उसके सोलैटियम सहित कब्जा लेने की तारीख से 6 प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई राशि पर ब्याज के भी हकदार होंगे। भूस्वामी-दावेदार भी अपने तर्कों के हकदार होंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
अंबाला, हरियाणा